रहे हैं । असम राज्य और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ और लक्षद्वीप को इन अनुदेशों का पालन करने की सलाह दी गयी है ।

Child Marriages in Rajasthan

1797. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) wheher it is a fact that child marriages are still being solemnised in many districts of Rajasthan;

(b) whether in recent months in majority of villages in the districts of Alwar, Jaipur Dausa Tonk; Sawwaimadhopur; Bundi and Kota child marriages were held and police party and teams of anti child marriage women organisations were not allowed to enter those villages; and

(c) if so, what measures Government have taken or likely to take to strictly enforce the Sharda Act in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) Registration investigation detection and prevention of crimes including the crime of child marriage is a responsibility of the concerned State Government. It is for the Government of Rajasthan to take neces sary steps to curb this evil practice in that State.

(c) Media support has been provided for creating an environment to discourage child marriages. Enforcement of the Child Marriage (Restraint) Act is being done by the Government of Rajasthan.

राज्यों के बीच भूमि-संबंधी विवाद

1798. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में भूमि-संबंधी विवाद चल रहा है;

(ख) इन विवादों में फंसी भूमि किन स्थानों पर अवस्थित है और उसका क्षेत्रफल कितना-कितना है, और

(ग) सरकार द्वारा इन विवादों का शीघ्र निपटान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है । (**नीचे देखिए**) ।

(ग) राज्यो के बीच सीमा-विवादों को संबंधित राज्य सरकारों के इच्छुक सहयोग द्वारा ही निपटाया जा सकता है और, इस दिशा में, केन्द्र सरकार सभी संभव सहायता संबंधित राज्यों को देती है ।

विवरण

अन्तर्राज्यीय सीमा-विवाद

(i) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा-विवाद

महाराष्ट्र राज्य ने कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा पर स्थित 814 गांवों तथा कर्नाटक राज्य ने 528 गांवों पर दावा पेश किया है ।

(ii) पंजाब हरियाणा सीमा-विवाद

यह विवाद "पंजाब पुनर्गठन अधिनियम" से उत्पन्न है ।

(iii) कर्नाटक-केरल सीमा विवाद

कर्नाटक द्वारा केरल-स्थित कसारगोड तालुक के एक हिस्से पर किए गए दावे पर यह विवाद केन्द्रित है ।

(iv) असम-नागालैंड सीमा विवाद

असम के 8000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर नागालैंड दावा करता है ।

(v) असम-मेघालय सीमा विवाद

असम और मेघालय के बीच विवाद नौगांव सैक्टर में खासी पहाड़ियों कामरूप